

प्रेषक,

अतर सिंह
उप सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तरकाशी।

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक: ३० जून, 2006

विषय: परिवार कल्याण उपकेन्द्र भवन ओडगांव, जनपद उत्तरकाशी के भवन निर्माण हेतु फीज की गयी धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके सं०-75/1/उपकेन्द्र/107/2001/3820 दिनांक 20.02.2004 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश सं०- 2898/ 20.2.93-10(20)97/ दिनांक 19.9.1998 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2006-07 में परिवार कल्याण उपकेन्द्र भवन ओडगांव, जनपद उत्तरकाशी के भवन निर्माण हेतु उत्तरांचल राज्य गठन के समय फीज की गयी धनराशि ₹० 4,84,000.00 (₹० चार लाख बीस हजार मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा। स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश की सभी शर्तें बंधावत रहेगी।

3- उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा निर्माण इकाई लॉ०नि०वि० को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनावधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाउचर संख्या व दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व शासन द्वारा नित्यव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- धनराशि उन्हीं योजनाओं में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृति की जा रही है।

7- स्वीकृत धनराशि को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय आय-व्ययक 2006-07 में अनुदान संख्या-12 लेखाशीर्षक 4211- परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-00-आयोजनागत- 101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा-00-91-उप केन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना), 24-गृह निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग की अशा० सं०-295/वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/2006 दिनांक 27.6.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अतर सिंह)

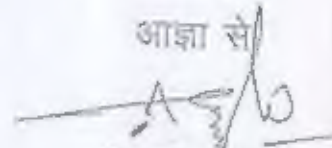
उप सचिव

संख्या- 447(1)/XXVII-S-2006-57/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
- 2- आयुक्त कुमायु/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल ।
- 3- स्टॉफ ऑफिसर मुख्य सचिव ।
- 4- जिला अधिकारी उत्तरकाशी ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ।
- 6- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी ।
- 8- क्षेत्रीय प्रबन्धक, समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तरांचल ।
- 9- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून ।
- 10- निजी सचिव मा० मुख्य मंत्री ।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग/एन०आई०सी० ।
- 12- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से



(अतर सिंह)
उप सचिव

प्रेषक,

अतर सिंह,

उप सचिव,

उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

उत्तरांचल देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक : 30 जून, 2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2006-07 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखरी जनपद चमोली के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-7घ/1/सी0एच0सी0/36/2003/18718 दिनांक 13.06.2006 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0-173/XXVIII/(S)-2005-179/2003 दिनांक 12.08.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखरी जनपद चमोली के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु संलग्नानुसार रु0 56,73,000.00 (रु0 छप्पन लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

- 1- प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य को अनुमोदित लागत तक ही रखा जाएगा । स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश की सभी शर्तें यथावत रहेगी ।
- 2- उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् निर्माण ईकाई क्षेत्रीय प्रबन्धक, समाज कल्याण निर्माण निगम को उपलब्ध कराई जायेगी । कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा । अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा ।
- 3- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाळचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।
- 4- स्वीकृत धनराशि का आहरण /क्रम वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लेखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व शासन द्वारा मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 5- धनराशि उन्ही योजनाओं / मदों में व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृति की जा रही है ।

6- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

7- उक्त व्यय वर्ष 2006-07 के आय-व्यय में अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 0301-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण(चालू अंश), 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0- 392/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2006 दिनांक 28.06.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(अतर सिंह)

उप सचिव

सं0-437(1)/XXV111-4-2006-179/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल, भाजरा देहरादून ।
- 2- आयुक्त कुमायु /गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल ।
- 3- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव ।
- 4- जिलाधिकारी, चमोली ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली ।
- 8- क्षेत्रीय प्रबन्धक, समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तरांचल ।
- 9- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून ।
- 10- निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री ।
- 11- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ नियोजन विभाग / एन0आई0सी0 ।
- 12- गार्ड फाईल ।

आज्ञा

(अतर सिंह)

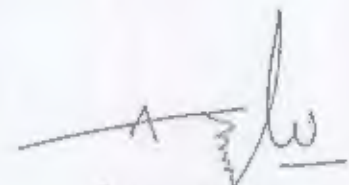
उप सचिव

शासनादेश सं०-437/XXV111-4-2006-179/2003 दिनांक 30-6-2006 का संलग्नक

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	निर्माण इकाई	लागत	गत वर्षों में अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2006-07 में स्वीकृत धनराशि
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखरी जनपद चमौली का भवन निर्माण ।	समाज कल्याण निर्माण निगम ।	156.73	100.00	56.73
योग			156.73	100.00	56.73

(रू० छप्पन लाख तिहत्तर हजार मात्र)



(अनुर सिंह)

उप सचिव

उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार अथवा रोजगार अपना कर जीविकोपार्जन हेतु राज्य सरकार द्वारा " सार्वभौम रोजगार योजना " प्रारम्भ की गई है, जिसके संचालन हेतु शासन के सम्यक विचारोपरान्त निम्न मार्ग निर्देश जारी किये जाने के मुझे निर्देश हुआ है :-

1- प्रस्तावना :-

उत्तरांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्तियों एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध जनशक्ति एवं सामाजिक पूंजी पर आधारित यह रोजगार योजना ऐसे इच्छुक शिक्षित, अर्द्धशिक्षित एवं अशिक्षित युवक/युवतियों, पुरुषों एवं स्त्रियों को लक्षित करती है जो स्थानीय रूप से स्वरोजगार अथवा रोजगार अपनाकर जीविकोपार्जन करना चाहते हैं।

2- योजना क्षेत्र:-

सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य का ग्रामीण क्षेत्र।

3- पात्रता :-

ग्रामीण परिवार का कोई भी एक वयस्क सदस्य जो केन्द्र अथवा राज्य द्वारा प्रायोजित एवं सहायित किसी भी ऋण सह अनुदान, स्वरोजगार/रोजगार योजना का लाभार्थी न हो एवं सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में नियमित रूप से सेवायोजित न हो, एवं स्वरोजगार हेतु इच्छुक हों।

4- आरक्षण :-

योजनान्तर्गत अनु0जाति तथा अनु0ज0जाति के लाभार्थियों का न्यूनतम प्रतिशत क्रमशः 18 व 3 रहेगा। कुल लाभार्थियों में कम से कम 33 प्रतिशत महिलायें तथा 3 प्रतिशत विकलांग होंगे।

5- अनुमन्यतायें :-

परियोजना प्रस्ताव के अनुसार चयनित क्रियाकलाप/गतिविधि के लिये प्रथम वर्ष में प्रति व्यक्ति रु0 7000/- (रु0 सात हजार मात्र) की सीमा तक अनुदान।

द्वितीय वर्ष में चयनित रोजगार क्रियाकलाप/गतिविधि की सफलता पर आधारित अधिकतम रु0 5000/- (रु0 पांच हजार मात्र) का प्रोत्साहन अनुदान।

तृतीय व अन्तिम वर्ष में चयनित रोजगार क्रियाकलाप/गतिविधि के सफल संचालन पर अधिकतम रु0 3000/- (रु0 तीन हजार मात्र) का प्रोत्साहन अनुदान।

परन्तु अनुदान की राशि किसी भी दशा में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी। परियोजना राशि के शेष भाग का निवेश लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जा सकता है अथवा वह इस हेतु बैंक से ऋण ले सकता है। बैंक ऋण की सीमा व्यक्तिगत

स्वरोजगार योजनाओं में यथा निर्धारित होगी। बैंक वित्त पोषण को प्राथमिकता दी जायेगी।

स्नातक अथवा उससे अधिक शिक्षित लाभार्थियों के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान कुल देय अनुदान का 10 प्रतिशत होगा।

6-रोजगार क्रियाकलाप/गतिविधियाँ:-

1. बागवानी
- 2-जड़ी बूटी एवं सस्य पादप कृषिकरण
2. वाणिज्यिक कृषि
- 3-पंचयत्की आधारित आर्थिक क्रियाकलाप
3. सूक्ष्म जल विद्युत योजना
4. शिल्प एवं कारीगरी पर आधारित आर्थिक क्रियाकलाप
5. खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन (value addition) सम्बन्धी आर्थिक क्रियाकलाप
6. कृषि, बागवानी, जड़ी-बूटी, पशुपालन हेतु निवेश सम्बन्धी सेवा व्यवसाय, एवं
- 7- अन्य कोई ऐसा क्रियाकलाप अथवा गतिविधि जिसे राज्य सरकार योजना के प्रयोजनार्थ सम्मिलित करे।

7-नोडल विभाग एवं जिले का नोडल अधिकारी:-

इस योजना का नोडल विभाग ग्राम्य विकास विभाग होगा। जिले में जिलाधिकारी इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे। क्रियान्वयन में सुगमता के लिये जिलाधिकारी कतिपय अथवा समस्त अधिकार मुख्य विकास अधिकारी के पक्ष में प्रतिनिधानित कर सकेंगे।

8-आवेदन एवं आवेदनों का निस्तारण :-

इच्छुक पात्र बेरोजगार व्यक्ति चयनित आर्थिक क्रियाकलाप/गतिविधि, उपलब्ध प्राकृतिक, सार्वजनिक व निजी संसाधनों एवं जनशक्ति व सामाजिक पूंजी का उल्लेख करते हुये आवेदन खण्ड विकास अधिकारी, रेखीय विभाग, जिला विकास अधिकारी अथवा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। चयनित क्रियाकलाप/गतिविधि की सम्भावनाओं के आधार पर रेखीय विभाग परियोजना प्रस्ताव 15 दिवस के भीतर सम्पूर्णता में जिलाधिकारी को स्वीकृतार्थ प्रस्तुत करेंगे। परियोजना प्रस्तावों के परीक्षण एवं उन पर संस्तुति हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न समिति विचार करेगी:-

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी

अध्यक्ष

परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए०

सदस्य सचिव

रेखीय विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी

सदस्य

क्रमशः—3